संपादकीय

हादसों की त्रासदी

मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में हुए भीषण अग्निकांड के बाद संसद में हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला। महाराष्ट्र की साझा सरकार में शामिल दो दलों (भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना) ने आरोप लगाया कि कंपाउंड में चलने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। आम इंसान के लिए यह समझना कठिन है कि अगर ऐसा है तो क्या वे दोनों पार्टियां इसकी जवाबदेही से बच सकती हैं? अत- यह अनिवार्य है कि इन दोनों दलों के सांसदों ने जो मुद्दे उठाए, उनकी पूरी जांच हो। इस बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या कि क्या कंपाउंड में बने रेस्टोरेंट्स के मालिकों की सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं से जान-पहचान के कारण वहां नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज किया गया?

ये कथित अनदेखी गुरुवार रात घातक साबित हुई, जब वन-एबव नामक रेस्तरां से भड़की आग के कारण एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। आरोप है कि कमला मिल्स कंपाउंड में स्थित ये रेस्तरां अवैध तरीके से बनाया गया था। अब यह भी सामने आया है कि इस कंपाउंड में ऐसे कई और रेस्तरां और पब गैरकानूनी ढंग से चल रहे हैं। और बात सिर्फ इस कंपाउंड की ही नहीं है। मुंबई में ऐसे और भी कई मिल कंपाउंड हैं, जिनमें या तो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स या फिर आवासीय परिसर बन गए हैं। यह जांच का विषय है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या इसके लिए उपयुक्त अनुमतियां ली गईं? अगर नहीं, तो फिर पुलिस और कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियां क्यों आंख मूंदे रही हैं? जरूरत इन तमाम बातों की तह तक पहुंचने की है।

मुंबई जैसी घटनाएं अग्नि-सुरक्षा उपायों पर अमल में लापरवाही या फिर बहुत-सी जगहों पर निर्माण संबंधी बुनियादी ढांचे के जर्जर होने का संकेत देती हैं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि हाल में मुंबई में आग लगने की घटनाओं काफी वृद्धि हुई है। सिर्फ इसी महीने की बात करें, तो पिछली 18 तारीख को शहर के साकीनाका इलाके में एक मिठाई दुकान में आग लगने से 12 मजदूरों की मौत हुई थी। उसके बाद 25 दिसंबर को दक्षिणी मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में एक 32 मंजिली इमारत में आग लगी, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं अग्नि-सुरक्षा उपायों पर अमल में लापरवाही या फिर बहुत-सी जगहों पर निर्माण संबंधी बुनियादी ढांचे के जर्जर होने का संकेत देती हैं। इनके मद्देनजर क्या यह जरूरी नहीं हो गया है कि शहर के रिहाइशी और व्यावसायिक इलाकों की हालत का पूरा जायजा लेते हुए अविलंब अग्नि-सुरक्षा एवं अग्निशमन के उपायों को पुख्ता बनाया जाए? उचित व्यवस्था और स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के बजाय समस्या का दोष %शहर की ज्यादा आबादी पर डालना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना होगा, जैसा कि एक सांसद ने कहा भी है।

विकल्पों की तलाश

ब्याज दरें बदल रही हैं। बैंकिंग बदल रही है। आम आदमी की समझ में सब कुछ नहीं आ रहा है। नासमझी या कम समझी के चलते उसकी जेब पर चपत लग रही है। अभी ही लघु बचत की ब्याज दरों में दशमलव 20 की कमी की गयी यानी पब्लिक प्रॉवीडेंट फंड पर जो ब्याज सालाना 7.8 प्रतिशत था, अब घटकर 7.6 प्रतिशत रह जायेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.5 प्रतिशत था, यह घटकर सालाना 7.3 प्रतिशत रह जायेगा। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर जो ब्याज दर 7.8 प्रतिशत थी, वह घटकर 7.6 प्रतिशत हो जायेगी। यानी आम आदमी ब्याज से कम कमा पायेगा। पर आफतें सिर्फ इतनी नहीं हैं। बैंक उपभोक्ताओं से तरह-तरह से वसूली करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक 2017-18 के दौरान करीब 2000 करोड़ रु पये दंड के वसूले जायेंगे इस बैंक के उन ग्राहकों से, जिनके खातों में बैलेंस न्यूनतम बैलेंस से नीचे चला जाता है।ब्याज दरों के लगातार कम होने के ही आसार हैं, क्योंकि ब्याज दरों का ताल्लुक होता है महंगाई से। महंगाई की दर अगर लगातार बढ़ती है तो ब्याज दरों का बढ़ना बनता है। इसका सामान्य-सा अर्थशास्त्र यह है कि अगर किसी ने किसी को सौ रु पये उधार दिये हैं। दिसम्बर 2017 में और उसकी वापसी अगले साल यानी दिसम्बर 2018 में होनी है, तो जाहिर है दिसम्बर 2018 में सौ रु पये की वैल्यू वह न रह जायेगी जो दिसम्बर 2017 में थी। यानी दिसम्बर 2017 में जो चीजें 100 रु पये की आयेंगी, एक साल बाद वे ही चीजें खरीदने के लिए 105 रु पये या ज्यादा चाहिए होंगे, ये पांच रु पये जो बढ़ते हैं, यह महंगाई दर होती है। तो सौ रु पये लेकर अगर कोई 105 वापस दे रहा है, तो महंगाई दर के चलते कुछ वापस हो नहीं पा रहा है। पांच रु पये से ऊपर जो दिया जायेगा, वही वास्तविक रिटर्न होगा। यानी अगर ब्याज दर सात प्रतिशत हो आठ प्रतिशत तब जाकर कुछ रिटर्न मिलेगा। नवम्बर 2017 में उपभोक्ता महंगाई सूचकांक 4.88 प्रतिशत रही है, ऐसी सूरत में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है। अगर महंगाई दर और गिरी तो ब्याज दर और गिरेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई पर नियंत्रणके लिए प्रतिबद्ध दिखायी देता है, ऐसी सूरत में वह पुराना दौर लौटकर न आयेगा, जिसमें महंगाई दर 12 प्रतिशत होती थी और ब्याज दर 19 प्रतिशत तक जाती थी। अब जरूरी है निवेशक रिटर्न के दूसरे रास्तों को देखें। मुचुअल फंड वगैरह में निवेश को देखें या दीर्घावधि में औसत रिटर्न 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत सालाना तक रहता है।

कटाक्ष/ कबीरदास

अलविदा-2017

अलविदा-2017। अलविदा! अलविदा, गौरी लंकेश को हमेशा के लिए सुलाने वाले साल। अलविदा, दाभोलकर, पानसरे तथा कलबुर्गी की तरह, उनके मामले में भी पुलिस को कोई लीड न मिल पाने के साल। ट्रोल सेना के गांधी की हत्या की तरह, इस हत्या पर भी खुशियां मनाने के और पीएम जी के एक बार फिर एकदम चुप्प लगा जाने के साल, अलविदा। केसरिया राज में राजपूताने में गोरक्षकों से लेकर, स्वच्छता-रक्षकों तक के हाथों आबादी घटवाने वाले साल; पद्मावती से लेकर हल्दीघाटी की लड़ाई तक, सारा इतिहास सुधरवाने वाले साल; बाबू लाल रैगर को नया गोडसे बनाकर पुजवाने और उदयपुर में अदालत पर तिरंगे की जगह केसरिया फहराने को राष्ट्रभक्ति बनाने वाले साल; तमाम गैर-केसरिया पब्लिक को और डराने वाले साल; अलविदा योगी को यूपी की गद्दी दिलाने वाले साल, अलविदा। मणिपुर और गोवा में दौड़ में दूसरे नम्बर पर रहकर भी, केसरिया को जिताने वाले साल, अलविदा। पंजाब में पिटकर भी मोदी जी को विजयी ब्रांड बनाए रखकर दिखाने वाले साल, अलविदा। उन्हें हिमाचल में एक और जीत दिलाने वाले, पर गुजरात में गद्दी बचाने से पहले, खूब पसीना निकलवाने वाले साल; चुनाव में विकास-फिकास सब भुलवा देने और नानी-नाना के अलावा पाकिस्तान याद कराने वाले साल; शाह को जीतकर भी हार की-सी फीलिंग दे जाने वाले साल, अलविदा। आडवाणी जी, जोशी जी से रिटायरमेंट का एक और साल कटवाने वाले, पर यशवंत को रिबेल बनवाने वाले साल, अलविदा। नोटबंदी की चोट पर, जीएसटी की चोट मारने वाले; किसानों को बागी बनाने वाले; रोजगार को जुम्ला बनाने वाले; नीतीश को केसरिया भक्त में पलटवाने वाले; एक मंत्री से संविधान को पलटने का एलान कराने वाले; राम सेतु पर अमरीकी मोहर लगवाने वाले; इकॉनामी का भट्ठा बैठाने वाले; महंगाई का जोर दिखाने वाले; शाह-जादे के हल्के में युवराज को मजे में तख्तनशीन कराने वाले साल, तू जा ताकि 2018 आए। जो तुझसे नहीं बना शायद वही कर पाए। हंसी न सही, पब्लिक के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट तो लाए।

पूरी दुनिया के बच्चे जिस पर लट्टू थे

हरजिंदर

गुजरते साल को बच्चों की नजर से देखिए। बच्चों के खेल और खिलौनों की नजर से। कुछ लोग 2017 को ब्लू व्हेल गेम का साल भी कहेंगे। यह सच है कि इस साल हमने एक ऐसे कंप्यूटर गेम के बारे में सुना, जो बच्चों को फंसा कर उन्हें आत्महत्या की ओर ले जाता है। हालांकि इसे खेल कहना भी गलत है, क्योंकि यह खेल नहीं, बच्चों को फंसाने का कुटा जनित दुश्चक्र है। कई खराब खबरों के कारण ब्लू व्हेल चर्चा में रहा है, लेकिन इसे 2017 की मुख्य घटनाओं में नहीं गिना जा सकता। बच्चों के लिहाज से देखें, तो इस साल की महत्वपूर्ण घटना है- फिजेट स्पिनर। हो सकता है कि आपने इसका नाम न सुना हो, लेकिन अपने घर में बच्चों से पूछिए, वे बेयरिंग पर चलने वाले तीन इंच के इस लट्टू के बारे में आपको बहुत कुछ बता देंगे। यह भी हो सकता है कि उनके खिलौनों में पांच-सात टूटे और साबुत फिजेट स्पिनर मौजूद भी हों। फिजेट स्पिनर 2017 में सफलता की ऐसी कहानी है, जिस पर दुनिया भर में तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन अपने देश में इस पर ज्यादा कुछ कहा या लिखा नहीं गया।

हालांकि इस खिलौने का पेटेंट 1993 में ही हो गया था, लेकिन इस साल अप्रैल के आसपास यह बाजार में आया और इससे पहले कि लोग समझ पाते, यह पूरी दुनिया के बाजारों में छा गया। इसकी कामयाबी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अमेजन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले 20 खिलौनों में 18 तरह-तरह के फिजेट स्पिनर ही थे। आप यू-ट्यूब पर जाकर सर्च में टाइप कीजिए- फिजेट स्पिनर। वहां आपको इससे जुड़े 74 लाख, 70 हजार से भी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे। फिजेट स्पिनर की कामयाबी सिर्फ इसकी लोकप्रियता में नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसने एक ही झटके में उन कई मिथकों को तोड़ दिया, जिन्हें पिछले एक दशक में खिलौना उद्योग ने बाजार का परम सच मान लिया था।

फिजेट स्पिनर बाजार में उस समय आया, जब बार्बी डॉल की बिक्री लगातार कम हो रही है। न ही वे नन्ही गाड़ियां ही ज्यादा बिक रही हैं, जिनमें कभी बच्चे दिन भर व्यस्त रहते थे। यहां तक कि लड़कों के लिए बनने वाली तरह-तरह की खिलौना बंदूकों ने भी कंप्यूटर और मोबाइल के शूटिंग गेम्स के आगे हार मान ली है। अभी कुछ ही दिन पहले तक यह कहा जाने लगा था कि अगर खिलौना उद्योग को अपनी पुरानी रौनक वापस चाहिए, तो उसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स को अपनाना ही होगा। कई कंपनियों ने यह किया भी, लेकिन बाजार की पुरानी रौनक नहीं लौटी। कई खिलौनों को समीक्षकों ने काफी सराहा, पर उन्हें लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज नहीं दिखा। इस बीच कहीं न कहीं यह भी मान लिया गया कि बच्चों के खेलों का भविष्य कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और बहुत हुआ तो प्ले स्टेशन वगैरह पर ही है। फिजेट स्पिनर ने एक ही झटके में ऐसी हर सोच को गलत साबित कर दिया।

इस खिलौने की खासियत यह है कि इसमें किसी बड़ी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। तकनीक के नाम पर इसमें बॉल-बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ है, जिसे पूरी दुनिया दो सदी से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल कर रही है। अगर आपके लिए अपनी धुरी पर घूमने वाले खिलौने का नाम पुराने जमाने के लट्टू और लत्ती है, तो उस लिहाज से फिजेट स्पिनर जरूर आधुनिक है। लेकिन जिसे हम आधुनिक तकनीक कहते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है।

फिजेट स्पिनर ने बच्चों को अपनी तकनीक से चमत्कृत भी नहीं किया। उसकी एक खूबी यह है कि वह बच्चों से किसी अतिरिक्त समय की मांग नहीं करता। उसने चुपके से ही बच्चों की वर्तमान जीवन शैली में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। उसे वे खाना खाते हुए, कंप्यूटर पर काम करते हुए, यहां तक कि पढ़ते हुए एक हाथ की उंगलियों पर नचा सकते हैं। शायद इसीलिए इसे बच्चों ने आसानी से अपना भी लिया। यह बच्चों को अपनी उंगलियों का संतुलन और अपनी रचनात्मकता आजमाने का मौका भी देता है। फिजेट स्पिनर एक और अर्थ में आदर्श खिलौना है। मजाक में ही सही, यह कहा जाता है कि अच्छा खिलौना वह है, जिससे बच्चे अपना दिल बहलाते हैं और बड़े चिढ़ते हैं। फिजेट स्पिनर इस कसौटी पर भी खरा उतरता है। इसके लोकप्रिय होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिका और यूरोप के कई स्कूलों ने इस पर पाबंदी लगा दी। वह भी उस समय, जब दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इन दावों का अध्ययन कर रहे हैं कि फिजेट स्पिनर ऑटिज्म के रोगियों के लिए मददगार है और बच्चे इससे ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं।

फिजेट स्पिनर की इस कहानी में एक बड़ी भूमिका चीन की भी है, जिसकी फैक्टरियों ने दिन-रात बल्क प्रोडक्शन करके इसे दुनिया के कोने-कोने में पहुंचा दिया। इसकी वजह से ही यह दुनिया के ज्यादातर बच्चों के हाथों में कुछ ही दिनों में पहुंच गया। भारत में किसी भी भीड़ भरे बाजार के फुटपाथ से आप इसे 60 से लेकर सौ रुपये तक में खरीद सकते हैं। यह कीमत निम्न मध्यवर्गीय परिवारों को भी बहुत परेशान करने वाली नहीं है। यहां अगर हम फिजेट स्पिनर की तुलना इससे पहले पूरी दुनिया में लोकप्रिय होने वाले रुबिक क्यूब से करें, तो मास प्रोडक्शन व व्यापार बाधाओं के न रहने की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। 80 के दशक में लांच हुआ रुबिक क्यूब आधे दशक से ज्यादा समय बाद ही भारतीय बाजार में उपलब्ध हो पाया था, जबकि फिजेट स्पिनर इस साल अप्रैल में चर्चा में आया और उसी महीने भारतीय बाजार में पहुंच गया। मई महीने में तो यह फुटपाथ तक पर बिकने लग गया था।

यह भी सच है कि फिजेट स्पिनर का मौजूदा क्रेज ज्यादा बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। जल्द ही बच्चे किसी और खेल या खिलौने पर लट्टू होने लगेंगे। लेकिन फिजेट स्पिनर ने यह तो बता ही दिया कि खेल और खिलौनों के लिए किसी महंगे शोध से ज्यादा जरूरत है बच्चों की दुनिया को लेकर एक सहज सामान्य समझ की। और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के बाहर भी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।

> राजनीति एक से दूसरे चुनावी परिदृश्य की ओर बढ़ती है, इसमें जो बदलाव दिख रहा है, वह अगले साल भी जारी रह सकता है।

नई सफाई मुहिम

बड़े बदलावों की आधारभूमि का साल

शंभुनाथ शुक्ल

साल 2017 का साल तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर आया, जिन पर बहस जरूरी थी। असहिष्णुता से लेकर धर्म और रोजाना के जन-जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे। यद्यपि असहिष्णुता की चर्चा 2015 से ही शुरू हो गई थी, जब उसी वर्ष 28 सितंबर को उ.प्र. में गौतमबुद्ध नगर के एक गांव बिसहाड़ा में गौ-वध की आशंका में मुहम्मद अख़लाक़ नामक व्यक्ति की हत्या हुई। तब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे बुद्धिजीवी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाने शुरू कर दिए। सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को आदेश दिए।

मगर इसी साल अप्रैल में हरियाणा के रहने वाले 15 लोग छह वाहनों में गायों को लेकर जयपुर से हरियाणा के नूंह जिले की ओर जा रहे थे। राजस्थान में बहरोड के पास इन्हें कथित गोरक्षकों ने रोका और इन पर हमला किया। इसके बाद खूब हंगामा मचा और संसद में भी बहस हुई, तब सबकी नींद खुली। इसके बाद प्रधानमंत्री की सीधी दखल पर हरियाणा में भाजपा सरकार ने 24 घंटे की गोरक्षा हेल्पलाइन बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षकों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल कर बैठ गए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने देखा है कुछ लोग पूरी रात एंटी-सोशल एक्टिविटी करते हैं और सुबह के वक्त गो रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे उनका डोजियर तैयार करें। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण नहीं मरतीं, बल्कि प्लास्टिक खाने से मरती हैं। गो सेवक और गो रक्षक अलग हैं। गायों का प्लास्टिक खाना बंद करा दें गो-सेवक, लेकिन गोरक्षक गायों के रक्षक नहीं बल्कि गोरखधंधा करने वाले लोग हैं। हालात सुधरे हैं। हरियाणा गोसेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने कहा है कि गोरक्षक गोवंश के साथ हिंसा की सूचना पुलिस को देंगे। खुद पहल नहीं करेंगे। यह एक शुभ संकेत है।

साल के जाते-जाते केंद्र सरकार तीन तलाक़ पर रोक हेतु मुस्लिम महिला विधेयक-2017 को लोकसभा में पारित करने में सफल रही। हालांकि इस मामले को कट्टर तत्वों ने धार्मिक और साम्प्रदायिक रूप देना चाहा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने स्वयं आगे बढ़कर पहल की। नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार सुरक्षा) विधेयक-2017 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें तीन तलाक को आपराधिक मामला करार देते हुए तीन साल तक कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है, 'हमने प्रस्तावित विधेयक पर विभिन्न लोगों से उनके सुझाव मांगे थे। इस्लाम में एक बार में तीन तलाक जैसा कुछ भी नहीं है।' उन्होंने कहा, कि नये कानून में तलाकशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी प्रावधान होंगे और यह कानून उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा।' इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक कहा था। इसके बावजूद परंपरा जारी रही । इसलिए सरकार यह विधेयक लाई है। साल 2017 जाते-जाते एक संदेश और दे गया है कि धर्म और सांप्रदायिकता के ऊपर होती है इंसानियत। और मानव मन सदैव इंसानियत की तरफ ही रहता है। यह वर्ष सबसे अधिक खराब गुजरा उन कथित बाबाओं, तांत्रिकों और ओझाओं के लिए, जो धर्म और सम्प्रदाय की आड़ में अंध-विश्वास तथा फरेब फैला रहे थे। धर्म सबको लुभाता तो बहुत है और इसी वजह से धर्म के बहाने करोड़ों-अरबों का कारोबार तो होता ही है, अपराध को भी कथित धर्मगुरु प्रश्रय देते हैं। पर इस साल अदालत ने पहल कर जिस तरह से धर्मगुरुओं पर लगाम डाली, वह एक सुखद संकेत है। पूरे विश्व में धर्म के नाम पर चलाए जा रहे गोरख-धंधे को रोकने की पहल हुई और धार्मिक आधार पर चल रहे आतंकवाद को रोका गया। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह रही कि जनता ने ऐसे धार्मिक ठिकानों का पक्ष लेने की बजाय उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को सही ठहराया। हरियाणा में धर्मगुरु बाबा राम-रहीम की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी हुई। अभी कुछ दिनों पूर्व गुरुग्राम के एक स्कूल में कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर हत्याकांड में स्कूल प्रबंधन ने स्वयं को अल्पसंख्यक स्कूल बताकर कानूनी दांव-पेंच से बचना चाहा, लेकिन ईसाई समुदाय ने उनका साथ नहीं दिया। इस मामले में पहले तो कंडक्टर अशोक की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने उस कंडक्टर को रिहा किया और उसी स्कूल में ही कक्षा ग्यारह के एक छात्र को पकड़ा। अब जिस छात्र को पकड़ा गया, वह सोलह साल का है, लेकिन उस पर मुकदमा एक वयस्क की तरह चलाने की बात हो रही है। आजकल रेप, हत्या आदि जघन्य अपराधों में 14 से 18 की उम्र के नाबालिग बच्चों की जैसी संलिप्तता पाई जा रही है, उससे लगता है कि ऐसे नाबालिगों के साथ एक वयस्क अपराधी जैसा सलूक हो। खास बात यह है कि आम लोग भी ऐसे फैसलों को सही मानते हैं। इन सब घटनाओं को देख कर लगता है कि इंसानियत ही सर्वोपरि है।

उत्तर प्रदेश

निवेश का माहौल तो बने

आर के सिन्हा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत सप्ताह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों को अपने राज्य में करने निवेश करने का न्योता देने गये। ऐसे में योगी जी उसी दिशा में चल पड़े हैं, जिस पर हरेक मुख्यमंत्री और सरकार को चलना ही चाहिए। कोई भी प्रदेश निजी क्षेत्र के निवेश के बिना चौतरफा विकास कर ही नहीं सकता। आपको देसी-विदेश निवेश तो आकर्षित करना ही होगा। इसी क्रम में आपको अपने राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण भी बनाना होगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी खुलकर आए। ये अपने आप में सुखद है कि अब अधिकतर राज्य अपने यहां निवेश लाने के लिए तगड़ी पहल कर रहे हैं। इनमें एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी है। इसका निश्चित तौर पर स्वागत तो होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो राज्य जितने ठोस कदम उठाएंगे निवेश को खींचने के लिए, उन्हें उतना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और देश के अंदर से ही प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी मिलेगा। यों तो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्रमशः मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और के. चंद्रशेखर राव में एक अद्भुत समानता भी है। ये दोनों अपने-अपने प्रदेश में निवेश लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और, महाराष्ट्र और गुजरात तो परम्परागत रूप से देश के दो इस तरह के राज्य हैं, जहां पर निवेश का वातावरण शुरू से ही रहा है। दरअसल, भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का रास्ता इन दोनों ही राज्यों से होकर गुजरता है। इस बीच,भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) हर साल एक सूची जारी करने लगा है जो यह बताता है कि देश के कौन से राज्य बिजनेस करने के लिहाज से उत्तम हैं। इस पूरी कवायद के पीछे एक मात्र लक्ष्य, राज्यों के बीच निवेश और विकास को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इस सूची में वे ही राज्य आगे निकल रहे हैं, जहां पर औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन की उपलब्धता है, लैंड रिकॉर्डस का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमर्शियल विवाद के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है , वगैरह-वगैरह।लेकिन उत्तर प्रदेशमें उद्यमियों की सबसे बड़ी चिंता राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर है। दुर्भाग्य रहा उत्तर प्रदेश का कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद गुंडागर्दी आम बात हो गई और सरकारी अफ़सरों तथा सरकारी पार्टियों के नेताओं द्वारा लूट की राशि बढ़ती ही गई। उत्तम प्रदेश को ''उलटा प्रदेश' बनाकर रख दिया विगत दो दशकों के शासकों ने। ऐसा भी नहीं है कि निवेशकों के बजट में ''चन्दा' और ''सुविधा शुल्क'का प्रावधान नहीं होता। जरूर होता है। लेकिन, दाल में नमक के बराबर! असीमित नहीं। अब कोई दाल से ज्यादा नमक ही मांगने लगे तो क्या अंजाम होगा? उत्तर प्रदेश भुगत रहा है, सबकी आंखों के सामने है यह!अगर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर ग़ौर करें तो इतना स्पष्ट है कि अगर प्रदेश सरकार निवेश करने की उत्सुक कंपनियों को तुरंत भूमि का अधिग्रहण करने में मदद करेगी, पर्यावरण अनुमति दिलवाने में विलंब नहीं करेगी, श्रम कानूनों का भ्रष्टाचार रहित अनुपालन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बिजली, पानी, सड़क और कुशल कामगारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और कर पण्राली की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा तो राज्य में मोटा निवेश आने लगेगा। ये कारक तो सभी राज्यों पर लागू होते हैं एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि हरेक कारोबारी का लक्ष्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही होता है। अधिक लाभ के लिए भारतीय कंपनियां हों या विदेशी सभी यही करने लगी हैं। बिहार में सत्तर के दशक में डॉ. जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए पांच औद्योगिक विकास प्राधिकरण बने थे। ये पटना, मुजफ्फरपुर, बोकारो, रांची और आदित्यपुर (जमशेदपुर) में बनाई गई थीं। इनमें से तीन तो झारखण्ड में चली गई। बिहार की दो अथॉरिटी पटना और मुजफ्फरपुर भी बंद प्राय हो गई हैं। इसलिए निवेशक भी भाग गए। अब पटना औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीन पर कहीं फ़िल्म निर्माता प्रकाश झा मॉल, होटल और मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं तो कहीं स्कूल खुल रहे हैं तो कहीं गाड़ियों के शो रूम। राज्य सरकार को अब राज्य में निवेश के नए सिरे से उपाय खोजने होंगे।